Government in locating the range at Baliapal in Orissa. A comprehensive plan has been drawn for proper resettlement and rehabilitation of the families likely to be displaced. The Orissa State Government has already started work in this regard.

National income

2573. SHRI KALPNATH RAI. Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what was the national income during 1985-86;

(b) the comparative figures for the two previous years, year-wise;

(c) what was the growth rate target fixed for 1985-86 and whether it has been fulfilled; and

(d) the growth rate target fixed for the current year and whether it is likely to be fulfilled?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI SUKH RAM): (a) According to the latest estimates released by the Central Statistical Organisation (CSO), the national income for the year 1985-86 was Rs. 195,707 crores at current prices and Rs. 60,143 crores at constant (1970-71) prices.

(b) The national income for 1983-84 and 1984-85 was Rs. 158,265 crores and Rs. 174.018 crores at current prices and Rs. 55.300 crores and Rs. 57,243 crores at constant (1970-71) prices respectively.

(c) and (d) No yearly targets of national income have been fixed in the Seventh Five Year Plan. The Seventh Five Year Plan, however, envisages a growth rate of 5 per cent as measured in terms of Gross Domestic Product (GDP) during the Plan period The growth rate of GDP achieved during the first year of the Seventh Plan i.e. 1985-86 was slightly higher at 5.1 per cent. For 1986-87, the 'Economic Survey' has anticipated the growth rate of national income between 4.5 and 5.5 per cent?

केनरा बैंक दानापुर

2574. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में जिला दानापुर के केनारा बैंक के प्रबंधक महिला उद्यमियों और उद्योगपतियों के लिए कठिनाई पैदा करते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिला उद्योग केन्द्र, पटना ने अपने पत्र सं० 2870, दिनांक 28 जून, 1986 द्वारा सिफारिश की थी कि शिक्षित बेरोजगार योजना के अन्तर्गत महिला उद्यमियों को जीप दी जायें और यदि हां, तो इस संबंध में सिफारिश किए जाने के बावजूद भी ऋण मंजूर न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि पिछले तीन-चार वर्षों से केनारा बैंक के अधिकारी उद्योगपतियों को परेशान कर रहे हैं और उद्योग का रुग्ण बना रहे हैं, यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) केनारा बैंक ने सूचित किया है कि यह सही नहीं है कि उसकी दानापुर, पटना शाखा के प्रबंधक महिला उद्यमियों और उद्योगपतियों के लिए कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं । महिला उद्यमियों और उद्योगपतियों के ऋण प्रस्ताव अर्थक्षमता के आधार पर मंजूर किये जाते हैं। बैंक ने इस आरोप से भी इंकार किया है कि उसके अधिकारी गत 3-4 वर्षों से उद्योगपतियों को तंग कर रहे हैं और इस प्रकार उद्योगों को रुग्ण बना रहे हैं ।

(ग) जी, हां, । संदर्भगत आवेदन विशिष्ट कारणों के साथ लौटा दिये गये थे । ऐसे ऋण प्रस्तावों का विस्तार से अध्ययन करने और उन्हें बैंक की सहायता योग्य न पाये जाने के बाद ही किया गया था ।